सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बम्बई में संयुक्त अधिवेशन

महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल

श्री. अलि यावर जंग

का

अभिभाषण

१२ फरवरी १९७३

माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यो,

विधानमंडल के इस इजलास में मैं आपका स्वागत करता हूँ।

२. जैसा कि आप जानते हैं लगातार तीन वर्ष से सूखे के कारण हमारा राज्य एक ऐसे सख्त संकट से गुजर रहा है जिसका हमको पहले कभी सामना नहीं हुआ था। मानसून की नाकामी से हमारे कई इलाकों में पैदावार पर बडा बुरा असर पड़ा, पानी का काल हो गया और जानवरों को तक दानाचारा नहीं मिल रहा है। इन इलाकों में करीब दो करोड़ आदमियों की आर्थिक जिन्दगी को बड़ा धक्का पहुँचा है। इससे पहले कभी भी हम पर ऐसा बुरा वक्त नहीं आया था और अब ये अकाल हमारे लिए जीने मरने का सवाल बन गया है।

३. अक्सर इलाकों में खरीफ की फसल तकरीबन पूरी की पूरी बर्बाद हो गयी और इस साल कोंकण और पूर्वी विदर्भ में तो धान की पैदावार तक को नुकसान पहुँचा है। जवार, बाजरा और मूंगफली की जो बरसाबरस बराबर पैदावार हुआ करती थी उसका भी करीब ७० फीसद हिस्सा जाया हो गया है। रबी की बरसात भी नहीं आयी और इसलिए रबी की फसल की भी उम्मीद बाकी नहीं रही है।

४. जो लोग सूखे का इस तरह शिकार बन गये उनको रोजगार और काम के जरिये कमाई दिलाने के लिए शासन ने बड़े पैमाने पर इमदादी काम शुरु किये। अकाल से जो आफत आयी उसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि आज सवा करोड़ से ज्यादा आदमी इमदादी कामों पर लगे हुए हैं। डर तो यह है कि यह तादाद और भी बढ़ेगी। जून में मानसून के आने तक बल्कि उसके भी कुछ देर बाद जब तक कि कृषि का काम मामूल के मुताबिक फिरसे शुरु न हो जाय, हमको बड़े कठिन वक्त से गुजरना होगा और अपनी कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए बड़ी हिम्मत, इरादे और मेहनत से काम लेना होगा।

५. रोजगार दिलाने के लिए जिन कामों का चुनाव हुआ है उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो पैदावारी या प्रोडक्टिव किस्म के काम हैं जैसे कि सॉइल कन्जर्वेशन, पर्कोलेशन टैंक, नहरें, नाला और कन्टूरबँडिंग, कम्युनिटी के कुएँ, लिफ्ट इरिगेशन और आमदरफ्त के जरिये। शासन के लिए यह भी जरुरी हो गया कि उसकी जो बड़ी स्कीमें थीं उनको भी पूरे जोर से शुरु कर दिया जाय और औसत दरजे के जो कार्यक्रम हैं उनके पेशगी काम चालू कर दिये जायँ। हमारी कोशिशों के कारण हमारी प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार के रेल्वे मिनिस्टर ने हाल ही में यह एलान कर दिया कि महाराष्ट्र में रेल्वे के चार प्रोजेक्ट शुरु कर दिये जायेंगे। आशा है कि उनपर काम जल्द शुरु हो जायगा।

६. पिछले वर्षों के मुकाबिल में इस साल पीने का पानी और दानेचारे का भी सख्त काल पड़ा है। ९ जिलों यानि औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर, सतारा, सांगली, पुणें, शोलापूर

और नासिक के कहतजदा इलाकों में पानी की कमी से बड़ी नाजुक हालत पैदा हो गयी। उससे दो चार होने के लिए पानी का जो भी जरिया हो उसकी तलाश की जा रही है और उसी सिलसिले में पुरानी बाउलियों को भी बड़े पैमाने पर फिर से ठीकठाक और ताजा किया जा रहा है। हमारे पास इस वक्त जो रिग्स हैं उनकी तादाद में इजाफा करने के लिए हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर से नये रिग्स खरीदने का इंतजाम किया गया है और उम्मीद है कि वो जल्द पहुँच जाएँगे।

७. जानवरों के दानेचारे में कमी पड़ जाने की वजह से राज्य सरकार ने बाज ऐसे जंगल के इलाकों में ढाई सौ कैम्प खोल दिये हैं जहाँ उनको पानी और चारा मिल सकता है और जहाँ साढ़े तीन लाख मवेशी पल सकते हैं। इनमें से दो लाख विदर्भ के जिलों में रक्खे जायंगे। सिंचाई के बाज इलाकों में शक्कर के कारखानों की मदत से जानवरों को बॅगासी, मोलास और शक्कर और यूरिया से बने हुए चारे की गिजा देने का इंतजाम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश और गुजरात के राज्यों से दानाचारा लाने का भी इंतजाम किया गया है।

८. लोगों को कम खाना मिलने के बुरे असर से बचाने के लिए उनको ताकद वाली गिजा पहुँचायी जा रही है और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा अकाल पड़ा उनमें सुखडी तकसीम की जा रही है जो बड़ी ताकतवाली गिजा है। इसके अलावा सहायता के कामों पर जो लोग लगाये गये हैं उनके इलाज और उनको बराबर दवा पहुँचाने का भी इंतजाम किया जा रहा है।

९. जो लोग बुढ़ापे या किसी और कमजोरी की वजह से ऐसे कामों का बोझ नहीं उठा सकते उनकी काम के बगैर भी इमदाद की जा रही है और कलेक्टरों को ताकीद की गयी है कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाय।

१०. हिन्द सरकार ने हमारे इस बुरे दिन में हमारी बड़ी हमदर्दी के साथ मदद की है। इस साल भर में उसने राज्य सरकार को १७ करोड़ का ग्रांट, काम चलाने के लिए ७ करोड़ पेशगी और फर्टीलाइजर और बीजों के लिए ४ करोड़ का थोडे दिन वाला कर्ज दिया है। १५ जनवरी तक खुद राज्य सरकार ने अकाल के कामों पर ३८ करोड़ २५ लाख रुपये खर्च किये हैं। मेरी हुकूमत हमारी प्रधानमंत्री की शुक्रगुजार है कि उन्होंने न फकत सहायता के इन कामों में हमारी मदद की बल्कि अपना कीमती वक्त निकाल कर खुद आयीं, हमारी मुश्किलों को खुद देखा और हमारी जनता के दुखदर्द में खुद अपनी हमदर्दी का इजहार किया।

११. इस बड़े बवाल में गैर-सरकारी संघठनों से भी मदद मांगी गयी है। मुख्य मंत्री की अपील पर हमारे उद्योगपति, फिलेन्थ्रापिस्ट, मालिकों और कामगारों के संघठनों ने जी खोलकर इमदाद पेश की। एक महाराष्ट्र स्केयरसिटी रिलीफ कमेटी भी बनायी गयी है जो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए रुपया जमा कर रही है। ये कमेटी इस काम के अलावा मेडिकल इमदाद और पानी के पहुंचाने के लिए टैंकर्स के जरिए से भी शासन की कोशिशों में हाथ बटा रही है। कमेटी ने रिलीफ फंड के लिए १० करोड़ रुपये का निशाना अपने सामने रखा है जिसमें से अभी तक एक करोड़ से ज्यादा रुपया जमा हो चुका है।

१२. एक तरह से हमारी ये मुश्किलें हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश और काम का एक बड़ा मौका भी साबित हुई हैं। उनकी वजह से हम बड़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब हो गये कि अपनी आप मदद करें। अब अगर अगले साल भी इत्तिफाक से बरसात हमारे साथ

ऐसी ही बेमुरौवती करे तो इस साल के कामों के कारण हमने अपने बचाव के लिए काफी साधन और सामान जमा कर लिया है। जमीन के अंदर के पानी का सर्वे करवा कर जमीन को उगाव के ज्यादा काबिल बनाने की कई स्कीमें आगे बढ़ायी गयी हैं और पानी को सिंचाई और उसकी तह को परकोलेशन के जरिए से ऊंचा करने का इंतजाम भी किया जा रहा है। हमको नाज है कि हमारी जनता ने अपनी इस मुसीबत में महाराष्ट्र के सच्चे प्राण और परंपरा को सामने रखकर अपनी इस कठिन आजमाइश का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया।

१३. खरीफ की बरसात के नाकाम होने पर हमने केन्द्र सरकार के एक इमर्जेंसी प्रोग्राम को जो कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए बनाया गया था इस उम्मीद से अपने सर लिया कि कमसे कम रबी की बरसात अच्छी होगी और खरीफ की फसल को जो नुकसान पहुंचा उसकी तलाफी हो सकेगी। केन्द्र सरकार ने उसके लिए हमको १६ करोड़ का थोड़े दिन वाला कर्ज दिया। इसी तरह १३ और स्कीमों के लिए उसने २५ करोड़ का कर्ज दिया जो १५ वर्ष में सालबसाल अदाई से फेर दिया जायेगा। शासन इन सारी स्कीमों को पूरे जोर से अमल में ला रहा है। बदनसीबी से रबी की बरसात ने भी अब हमको मायूस कर दिया। अगर ये न होता तो इन सारी स्कीमों का हमको पूरा पूरा फायदा पहुंच सकता था मगर ये न होने पर भी हम उनसे बहुत दिनों तर फायदा उठा सकेंगे और उनसे उन इलाकों की कृषि में स्थिरता पैदा होगी जहां बरसात का कभी भी यकीन नहीं है।

१४. इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन ने महाराष्ट्र के कृषि विकास के क्रेडिट प्रोजेक्ट को जो मंजूर किया था वो ३० जनवरी १९७३ से अमल में आ चुका है। उसके बदौलत टयूब वेल, पंप के साथ डग वेल, मौजूदा कुओं को बेहतर बनाने, लिफ्ट इरिगेशन और सिंचे हुए रकबों के विकास के लिए हमको ३० मिलियन डॉलर मिल सकेंगे। मार्च ७४ के आखिर तक आशा है कि १२ हजार ८ सौ नयी बाऊलियां तैयार हो जायेंगी। हमको उम्मीद है कि यह काम हमारे लिए एक ऐसी नींव पैदा कर देगा जो हमको अपने सालाना अकाल का पूरी तरह मुकाबला करने के काबिल बना देगी। ये सारा कार्यक्रम राज्य के लैण्ड डवलपमेंट बैंक के जरिये से चलाया जायगा और उसके लिए जरुरी कदम उठाये गये हैं जैसा कि लैण्ड डवलपमेंट एजेंसी और जी.एस.डी.ए. का कायम करना और उन तमाम अदारों को माली और बुनियादी तौर से मजबूत बनाना जो इन कामों को आगे बढाने में हाथ देंगे।

१५. सितम्बर ७२ से राज्य में गिजा की हालत इसलिए नाजुक हो गयी कि जिलों में अनाज के स्टाक ज्यादा काम में लाये जाने से कम होते गये। उनके फिर से बढ़ाने के लिए शासन ने धान, चावल, जवार और नागली को मुकामी काश्तकारों से मोनोपली प्रॉक्यूरमेंट के जरिये हासिल करने की स्कीम को जारी रक्खा है। हम हिंद सरकार से भी मुतालिबा करते जा रहे हैं कि राज्य को ज्यादा अनाज तकसीम करे मगर अभी तक वो उतना अनाज हमको नहीं दे सकी जितना कि हमको चाहिए। आशा है कि उसकी मिकदार और उसके वक्त पर पहुँचने का बेहतर इंतजाम हो सकेगा।

१६. राज्य सरकार ने शक्कर की उपज को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये हैं। उसने यह तय किया है कि शक्कर के ऐसे नये कारखानों की पूंजी में हिस्से ले जिनको १९६९–७० और उसके बाद लाइसेंस दिया गया है। इस तरह सरकार हर कारखाने में ४५ लाख और पिछड़े इलाकों के हर कारखाने में ६० लाख के हिस्से लेगी।

१७. बरसात के न पड़ने से मुश्किलों के होते हुए भी शासन ने १९७२–७३ की योजना को पूरा किया । इस साल की योजना के बारे में अंदाजा है कि प्लानिंग कमीशन ने जो २०५ करोड़ रुपये मंजूर किये थे उससे कुछ ज्यादा ही खर्च होगा । अगले साल की योजना को जो इस पंच-वर्षीय योजना का आखिरी साल होगा हमारे १५ पाइंट प्रोग्राम पर ढ़ाला जायगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलें और उनकी ऐसी बुनियादी जरुरतें पूरी हों जैसे पीने का पानी, इब्तेदायी तालीम, छोपड़पट्टियों को हटाना और उनको रहने को घर देना । इनमें से सबसे बढ़कर उन कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनसे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों । इसलिए भी सिंचाई की स्कीमों को वक्त से पहले पूरा करने की कोशिश की जा रही है और आशा है कि मई १९७३ तक ६९ छोटी सिंचाई के काम, ८ औसत सिंचाई के काम और ४१५ लिफ्ट इरिगेशन की स्कीमें तैयार हो जायंगी जिनसे एक लाख ८८ हजार हेक्टर जमीन को पानी पहुंच सकेगा । इनके अलावा मुकामी क्षेत्र में करीब १,५०० छोटे सिंचाई के काम ३१ मार्च १९७३ तक पूरा कर देने का इरादा है जिनसे ६५ हजार हेक्टर और जमीन को भी पानी पहुंच सकेगा । अंदाजा है कि इन सारी स्कीमों से रोजगार के पैदा करने में काफी इजाफा होगा ।

१८. सिंचाई, बिजली की कूबत, पानी की सरबराही और कृषि विद्यापीठ की स्कीमों की वजह से खेती की जमीनों के काफी बड़े रकबे हासिल करने पड़ेंगे और कई गांवठान पानी के तले आ जायेंगे । शासन ने तय किया है कि खेती करने वाले जो इस तरह बेघर हो जायंगे उनको घर बनाने और काश्त करने के लिए दूसरी जमीन दी जाय । इस सिलसिले में अभी तक डायरे-क्टोरेट ऑफ रिसेटलमेंट के जरिये से ३३ हजार खान्दान दूसरी जमीनों पर आबाद कर दिये गये हैं और बाकी काम हो रहा है ।

१९. देहात में भूमिहीन कामगारों के खान्दानों को बिला कीमत घर बनाने के लिए जमीन दिलाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरु किया गया है जिसके जरिए ३ वर्ष में ५ लाख मकानों के लिए जमीन तकसीम कर दी जायगी । उसी तरह बेजमीनों को भी जमीन बांटी जायगी ताकि वो अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें ।

२०. लोगों को नल का पानी पहुँचाने का काम भी काफी आगे बढ़ गया है । सन् १९७२–७३ में १,२५१ ऐसी स्कीमों पर काम जारी रहा और १९७३–७४ में ऐसी ही ८९५ बरायन्दा स्कीमों के लिए नई स्कीमों के अलावा रुपया फराहम किया जायगा । इस कार्यक्रम से मिलाजुला कर हमारे जिला परिषदों ने कुओं की खुदाई का प्रोग्राम अपने जिम्मे लिया है ।

२१. बृहत्तर बंबई में आसानियां पैदा करने के कामों में साफ सुथरे दूध की सरबराही को शासन ने पहला दरजा दिया है। धुलिया में एक आधुनिक डेअरी बन चुकी है जिसकी रोजाना २ लाख लिटर दूध की समायी है और वहां से प्रोसेस किया हुआ दूध और दूध से बनायी हुई चीजें बंबई लायी जाती हैं। आपरेशन फ्लड के तहत ये तय पाया है कि एक और डेअरी कुर्ला में कायम की जाय जो देश की सबसे पहली मदर डेअरी होगी और जिसकी समायी रोजाना ४ लाख लिटर होगी। अंदाजा है कि अगस्त १९७३ तक यह तैयार हो जायगी। जब इन डेअरियों के साथ साथ आरे और वरली की डेअरियों को बढ़ाने का काम भी पूरा हो जायगा तो बृहत्तर बंबई में दूध की सरबराही रोजाना ११ लाख लिटर तक पहुंच जायगी। सहकारी क्षेत्र में जलगाव डेअरी का एक और प्रोजेक्ट है जिसकी समायी रोजाना ५० हजार लिटर होगी। इस फीडर डेअरी में

ऐसी मशीनरी भी होगी जो भरपूर मौसम में मलाई रहित दूध का पाउडर और मसका भी बना सकेगी। आशा है कि ये डेअरी दो वर्ष के अंदर काम करना शुरु कर देगी।

२२. शहरी इलाकों में दूसरी आसानियों को बढाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। बंबई में पानी की सरबराही और सिवरेज की स्कीमों के बारे में वर्ल्ड बैंक की टीम मुआफिक रिपोर्ट पेश कर दी है। दोनों की लागत अंदाजन ४२१ करोड रुपये होगी और हमें अब इंटर नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की इमदाद के बारे में तसफीहे का इंतजार है। वाटर सप्लाइ प्रोजेक्ट के जरिये जो पानी तकसीम होगा उसके लिए राज्य सरकार ने बंबई के म्युनिसिपल कार्पोरेशन को ६ करोड़ ५० लाख का ग्रांट देने का तसफीहा किया है। सरकारने तमाम म्युनिसिपल कार्पोरेशनों और कौन्सिलों को ७ अप्रैल और फिर १२ अक्तूबर १९७२ को मशविरा दिया कि मई १९७३ के अखिर तक पीने के पानी के काल पर काबू पाने के लिए वो क्या तदबीरें अख्तियार करे। डिविजनल कमिशनरों को ४० लाख रुपये इस गरज से दिये गये हैं कि म्युनिसिपल कौन्सिलों में कुओं को डोंगा करने, नई बाउलियां खोदने, टँकर्स के किराये और पानी की सरबराही की इमर्जेंसी स्कीमों के लिए तकसीम किये जायं। इस साल के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर एल.आय.सी. ने ८९ लाख रुपये पानी की सरबराही की २५ चालू स्कीमों के लिए कर्ज दिये हैं।

२३. महाराष्ट्र के समुंद्री किनारे के करीब जहां जहां गहरे पानी में मछलियों का शिकार हो सकता है उसका सर्वे अप्रैल १९७२ में शुरु कर दिया गया। आशा है कि महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट का नया कार्पोरेशन इस काम को जारी रक्खेगा और उसके साथ साथ मछुओं को गहरे और किनारे के करीब पानी में मछली पकड़ने और उनके मार्केट और प्रोसेस करने और मुल्क से बाहर भेजने में मदद देगा।

२४. शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर खासतौर से ध्यान दिया गया है कि शिक्षा को फैलाया जाय और बेहतर भी बनाया जाय। शिक्षक विद्यार्थी रेशियो को बेहतर बनाने के लिए १९७१-७२ में ४८८५ और १९७२-७३ में ६५९२ नये प्राइमरी टीचर मुकरर किये गये ताकि १६ हजार शिक्षकों की जो कमी थी उसे एक हद तक पूरा किया जा सके। अब प्राइमरी मदरसों में ट्रेनिंग पाये हुए ग्रेजुअट हेडमास्टर मुकरर किये जा रहे हैं। ५ वें, ६ ठे और ७ वें स्टैन्डर्डस् हाय स्कूलों के साथ मिला दिये गये हैं जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग पाये हुए ग्रेजुअट शिक्षक मिल सकेंगे। १९७२-७३ का युनेस्को का वर्ल्ड शाहरेजा पहलवी प्राइज महाराष्ट्र को उसके एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के लिए मिला जो सारे राज्य में केन्द्र सरकार की जायद इमदाद से फैलाया जा रहा है। अनपढ़ों के लिए फंक्शनल लिटरेसी और आमतौर से शिक्षा के लिए रेडियो और टी. वी. के इस्तेमाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। टेक्नीकल एजुकेशन का महकमा सिविल, मेकेनिकल और एलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के सैंडविच किस्म के डिप्लोमा कोर्स और करसपॉन्डेन्स कोर्स भी चला रहा है। बंबई यूनिवर्सिटी भी आर्टस् और कामर्स के करसपॉन्डेन्स कोर्स चला रही है। मुख्य मंत्री की सदारत में एक ऊंचे पाये की कमेटी कोशिश कर रही है कि सायंस के रिसर्च में समन्वय पैदा करे और रिसर्च के नतीजों को काम पर लगाये। हमारी यूनिवर्सिटियों की बुनियाद को बड़ा करने और एक ही साचे में ढ़ालने के लिए एक मुक्कमल कानून तैयार किया गया है। ये भी तजबीज है कि अगर हिन्द सरकार और प्लानिंग कमीशन मंजूर करे तो दो और यूनिवर्सिटियां एक विदर्भ और दूसरी उत्तर महाराष्ट्र में कायम की जांय ताकि पुणे और नागपुर यूनिवर्सिटियों

पर एफिलियेटेड कालेजों का इस वक्त जो बोझ है, वो हल्का हो जाय। कोशिश ये भी की जा रही है कि राज्य में एक संस्कृत विद्यापीठ केन्द्र सरकार की मदद से कायम किया जाय। प्राइमरी और सेकेन्डरी शिक्षकों को जो १९४७ के बाद सरविस से अलग हो गये और जिनको १९६१ के पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिला अब उनपर वो स्कीम लागू कर दी गयी है।

२५. पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए हुकूमत ने कई कार्यक्रम शुरू किये हैं जिनमें सबसे अहम एरिया डेवलोपमेंट यानि आश्रम काम्पलेक्स, ट्राइबल डेवलोपमेंट कारपोरेशन और वो जिलेवारी कमेटियां हैं जो पिछड़े वर्गों और आदिवासियों की शिकायतों की दरियाफ्त के लिए कायम की गयी हैं। विधान मंडल को जो यकीन दिलाया गया था उसके मुताबिक एक कमेटी बना दी गयी है जो छुआछूत हटाने और हरिजनों को सताये जाने और शोषण से बचाने की तदबीरें पेश करेगी। श्री पागे उसके अध्यक्ष हैं।

२६. झोपड़पट्टियों और गंदी बस्तियों की बेहतरी के लिए शासन ने एक अलहदा बोर्ड कायम किया है। उसका ये काम होगा कि ऐसी बस्तियों में पानी, बिजली, आमदरफ्त और सफाई की आसानियां पहुंचाएँ।

२७. मेरी हुकूमत अपनी इस कोशिश में कामयाब हुई कि नीचे और बीच दरजे की आमदनी पाने वालों को घर बनाने के लिए एल.आइ.सी. महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को ३ करोड़ का कर्ज दे जिसका एल.आइ.सी. ने यकीन दिला दिया है। राज्य सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है कि पिछड़े वर्गों की सहकारी हाउसिंग सोसाइटीज के मेम्बरों के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड से सरकारी गारंटी पर ८६ लाख का कर्ज दिला कर ११८० घर बनवा दे। इस साल १५०० घरों का जो अंदाजा किया गया था वो आशा है कि पूरा हो जायगा।

२८. कपड़ों की बीमार गिरनियों के बंद हो जाने ने हुकूमत को बहुत परेशान कर रक्खा था। इस वक्त वो २५ ऐसी गिरनियों को चला रही है जिसकी वजह से ५० हजार कामगार रोजगार पा रहे हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि सन १९७२ में उनमें से बाज तो मुनाफे के साथ भी चलाये गये। राज्य सरकार की इस पॉलिसी के मुताबिक के गिरनियों और कारखानों को चलाने में कामगारों का भी हाथ रहे। उनके नुमायंदों को गिरनियों की कमेटियों में शरीक किया गया है और महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन के बोर्ड पर तो एक कामगार डायरेक्टर भी मुकरर किया गया है।

२९. जैसा कि आप जानते हैं शासन की ये भी पॉलिसी है कि उद्योग को पिछड़े इलाकों में फैला दें। इस नीति को एमआइडीसी और एसआइसीओएम जैसा खास इदारों और पैकेज इनसेंटिव के जरिये से आगे बढ़ाया जा रहा है। एमआइडीसी ने अभी तक २५ ऐसे इन्डस्ट्रीयल इसटेट कायम कर दिये हैं और २० और ऐसे इलाके बनाने की तजबीज है।

३०. धात के खानों की प्रोस्पेक्टींग और दरयाफ्त की स्कीमें जो डायरेक्टोरेट ऑफ माईनिंग जिऑलोजी धात वाले इलाकों में चला रही हैं, जारी रक्खी जा रही हैं। कोंकण और जलगांव-नासिक-धुलिया के इलाकों के लिए दो सर्वे यूनिट इस गरज से बनाये गये थे उन्होंने रत्नागिरी और जलगांव में अपना काम शुरू कर दिया है।

३१. राज्य में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसे मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ देखता चला आ रहा हूं और मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि महाराष्ट्र अब

भी उन राज्यों में से है जिन्होंने इस मैदान में सबसे ज्यादा काम किया है। आपने जरूर खुद भी देखा होगा कि ये काम समाज के सारे भागों यहां तक कि झोपड़पट्टी वालों तक भी पहुंच चुका है जिनके लिए परिवार नियोजन आसान नहीं है। राज्य में अभी तक २ मिलियन से ज्यादा बंध्यीकरण के आपरेशन हो चुके हैं मगर अब भी इसकी सख्त जरूरत है कि इस कार्यक्रम को और भी जोर और पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ाया जाय।

३२. महाराष्ट्र में आमदरफ्त के जरियों को बेहतर बनाने के काम में काफी तरक्की हुई है। १९७२-७३ में अंदाजा है कि नेशनल हाइवेज पर १३ करोड़ रुपये खर्च होंगे। १९७३-७४ के दौरान में बम्बई–मालसेटघाट–अहमदनगर का हाइवे खुल जायेगा। १९७२-७३ में रेवास-रेडी के समुद्र के किनारे हाइवे के सर्वे का काम शुरू किया गया है। पच्छिमी साहिल के हाइवे से कोंकण के उन इलाकों की आर्थिक उन्नति में मदद मिलेगी जहां अभी तक पहुंचना मुश्किल था। रत्नागिरी और जलगांव के कुल मौसमी हवाई अड्डे भी तवक्को है कि मई १९७३ तक तैयार हो जायंगे। धुलिया और उस्मानाबाद में भी ऐसे ही हवाई अड्डे डकोटा किस्म के पैसेंजरी हवाई जहाजों के लिए बनाये जा रहे हैं।

३३. नये बंबई शहर का काम भी आगे बढ़ा है। थाणा क्रीक का पुल जहां खतम होता है उसके करीब एक टाउनशिप वाशी में और पनवेल क्रीक पर एक पुल बनाने का काम भी हाथ में लिया गया है। शाहबाज में सेन्ट्रल बिजनेश डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। इसी तरह हमारे दूसरे शहरी इलाकों के अतराफ भी नये टाउनशिप बनाये जा रहे हैं और नये औरंगाबाद का प्रोजेक्ट करीब में शुरू कर दिया जायगा और नासिक के पास एक नये टाउनशिप का सर्वे भी खतम होने को है।

३४. आप जानते हैं कि शासन की ये कोशिश है कि महकमों के लिए बम्बई के शहर में मकानों के किराये पर जो खर्च हो रहा है उसे सरकारी इमारतों की तामीर से घटा दिया जाय। सचिवालय के सामने जो कई मंजिलवाली सरकारी इमारत बनायी जा रही है वो अंदाजन मार्च १९७४ तक तैयार हो जायगी और उसकी चार मंजिलें तो बहुत जल्द इस्तेमाल में आ जायंगी। नये बम्बई के शहर में भी सरकार ने तय किया है कि एक इमारत दफ्तरों के लिए तामीर की जाय और इरादा है कि बाज वो महकमें जो इस समय बम्बई शहर में किरायों के मकानों में काम कर रहे हैं वो वहाँ भेज दिये जांय।

३५. मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हुकूमत की कोशिशों से देहात में बिजली पहुंचाने का काम बहुत आगे बढ़ रहा है। एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के क्रैश प्रोग्राम की वजह से तवक्को है कि १,३५१ और गांव में बिजली पहुँच जायगी और १९७३-७४ तक हमारे राज्य की आबादी के ७० फीसद को बिजली मिल सकेगी। सन् १९७२-७३ तक एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने २ लाख ४० हजार सिंचाई पंपों को बिजली से बदल दिया।

३६. विधान मंडल का ये इजलास खासतौर से इस लिए तलब किया गया है कि बजट मंजूर किया जाय। उनके अलावा कानून के तीन मस्विदे विधान सभा की मंजूरी के लिए पहले ही से पेश हैं यानि :—

1. The Maharashtra Slum Improvement Board Bill, 1972.

2. The Maharashtra Public Services Subordinate Selection Boards Bill, 1972.

3. The Indian Partnership (Maharashtra Amendment) Bill, 1972.

अब उनके अलावा १३ और मस्विदे इस इजलास में पेश किये जायेंगे यानि :—

(1) A Bill to amend the Bombay Public Trusts Act, 1950.

(2) A Bill in respect of Pandharpur Temple based on the recommendations of the Nadkarni Commission.

(3) A Bill to amend the Jamshetjee Jejeebhoy Baronetcy Act, 1915 and Petit Baronetcy Act, 1893.

(4) Bombay Village Panchayats (Postponement of Elections) Bill—to provide for conversion of Ordinance.

(5) A Bill to regulate and control the working of the Chit Funds in the State.

(6) A Bill to amend the Bombay Sales Tax Act, 1959.

(7) A Bill to amend section 14 of the Bombay Sales Tax Act, 1959 and validation provision to provide for conversion of Ordinance.

(8) A Bill to amend the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942.

(9) A Bill to amend section 9 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958.

(10) A Bill to amend the Bombay Building Repairs and Reconstruction Board Act.

(11) A Bill to extend the life of Bombay Rents, Hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947.

(12) A Bill to amend the Maharashtra Apartment Ownership Act, 1970.

(13) A Bill to amend the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 and Rents Control Acts.

३७. माननीय सदस्यों, मैंने आपके सामने अपनी हुकूमत की उन सारी नीतियों और कार्यक्रमों को पेश कर दिया है जिनको उसने अख्तियार किया है और मुझे यकीन है कि उसको उनके आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग हासिल होगा।

जय-हिन्द